क्या भगवा चुनौती का सामना कर पाएगा 'जनता परिवार'

मनोज कुमार झा/वीणा भाटिया

आज नीतीश कुमार भाजपा को साम्प्रदायिक बताते हुए उसे अछूत और दुश्मन मानकर चल रहे हैं, पर क्या भाजपा के साम्प्रदायिक चरित्र के बारे में उन्हें आज पता चला है ? जब भाजपा का नेतृत्व आडवाणी के हाथों में था, तो क्या वह साम्प्रदायिक नहीं थी ? अयोध्या में राममंदिर का अभियान किसने चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ और देश भर में साम्प्रदायिक दंगे हुए। जाहिर है, लालू-मुलायम-नीतीश जैसे नेताओं को साम्प्रदायिकता के ख़तरे से कोई लेना-देना नहीं है, इन्हें तो मतलब है अपनी कुर्सी बचाए रखने से, अब जिस तरह ख़तरा मंडरा रहा है और इसी आसन्न ख़तरे से बचने के लिए ये एक हो रहे हैं। लेकिन क्या इनकी एकता बन भी पाएगी और बनी तो कब तक चल पाएगी, यह सवाल महत्त्वपूर्ण है।

भगवा चुनौती का मुकाबला करने के लिये जनता परिवार ने महाविलय की घोषणा कर दी है। अब समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की अगुआई में बार-बार टूटे और बिखरे दल फ़िर एक बार सत्ता पर काबिज़ होने की उम्मीद में एक होने जा रहे हैं। औपचारिक घोषणा हो चुकी है। समाजवादी जनता दल के नाम से समानधर्मी पार्टियों का यह महाविलय हुआ है। यह अलग बात है कि पार्टी के झंडे ओर चुनाव चिह्न पर अभी सहमति नहीं बनी है। पर यह भी हो जाएगा, ये अलग बात है कि इस पर रार भी हो। कुल मिला कर यह महाविलय भगवा उभार के कारण हाशिए पर पड़ते जा रहे उन दलों के लिए ज़रूरी हो गया था, जो पहले कभी एक रहे थे, पर सत्ता में वर्चस्व की लड़ाई और व्यक्तिगत महत्तवाकांक्षाओं ने जिन्हें अलग कर दिया। लालू, नीतीश, मुलायम जैसे क्षत्रपों नें यूपी-बिहार में अपनी सत्ता कायम रखी, पर भगवा की जीत और मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही इन्हें अपनी सत्ता पर ख़तरा मंडराता साफ़ दिख रहा हैं। इसलिये महाविलय का यह निर्णय 'जनता परिवार' के नेताओं को लेना ही पड़ा।

उल्लेखनीय है कि मुलायम सिंह बहुत पहले से ही गैरभाजपा और गैरकांग्रेसवाद के आधार पर इस तरह का एक गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने काफ़ी कोशिश की, पर कतिपय दलों और नेताओं के उत्साह नहीं दिखा पाने के कारण उनकी योजना मूर्त रूप नहीं ले सकी। लेकिन इस बार सवाल अपने अस्तित्व को बचाने का है, इसलिए सहमति बन गई है और एक नई पार्टी आकार लेने जा रही है। इस पार्टी में फ़िलहाल सपा, राजद, जेडीयू (एस) और हरियाणा की इनेलो शामिल है, जिसे चौटाला पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी ही ये दल अपना झंडा और चुनाव चिह्न भी तय कर लेंगे। सामने बिहार विधानसभा चुनाव है। समझा जा रहा है कि इस चुनाव में यह नई पार्टी भाजपा का मुकाबला करने के लिये चुनाव मैदान में उतरेगी। कहा जा रहा है कि जनता परिवार के अलग-अलग दलों का विलय इसलिए भी जरूरी हो गया था, क्योंकि मोदी देश में सर्व सत्तावादी नीतियां चलाने की कोशिश कर रहे हैं। साम्प्रदायिकता से लड़ना भी इसका मुख्य उद्देश्य बताया गया है।

भूलना नहीं होगा कि सबसे पहले जनता पार्टी का गठन इंदिरा गांधी की सर्व सत्तावादी प्रवृत्तियों के ही ख़िलाफ़ हुआ था। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस विरोधी कुछ दलों ने जिनमें समाजवादी प्रमुख थे, जनता पार्टी की आधारशिला रखी, जिसमें जनसंघ यानी वर्तमान में भाजपा के नेता भी शामिल थे और साथ ही कांग्रेस के वो नेता जो इंदिरा गांधी की सर्वसत्तावादी प्रवृत्तियों के खिलाफ़ थे। उस समय इमरजेंसी से त्रस्त देश की जनता ने जनता पार्टी को भारी बहुमत से जीत दिलाई, पर जल्दी ही नेतृत्व और पार्टी पर वर्चस्व को लेकर विवाद सामने आने लगे और सरकार अपना टर्म पूरा नहीं कर सकी। इंदिरा गांधी दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ गईं। उल्लेखनीय है कि क्या समाजवादी उस वक्त जनसंघ के साम्प्रदायिक चरित्र को नहीं समझ पाए थे ? क्या जाप्रकाश नारायण जिन्हें 'लोकनायक' की पदवी से विभूषित किया गया, नहीं जानते थे कि जनसंघ की विचारधारा कितनी ज़हरीली और ख़तरनाक है ? यह एक ऐसा सवाल है, जिस पर विचार करना चाहिये।

इसके बाद, राजीवगांधी जब बोफोर्स घोटाले में फंसे तो भ्रष्टाचार विरोध के मसीहा बन कर उभरे उन्हीं के मंत्रिमंडल में शामिल विश्वनाथ प्रताप सिंह। उन्होंने जो जनमोर्चा बनाया, उसमें जनता पार्टी के बहुतेरे घटक दल शामिल हो गए। लेकिन तब तक जनसंघ ने भारतीय जनता पार्टी के रूप में नया अवतार ले लिया था। कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार से उबी हुई जनता ने कांग्रेस को चुनाव में हरा दिया। राजीव गांधी की मिस्टर क्लीन की छवि धूलि-धुसरित हो गई, लेकिन वीपी सिंह को सरकार बनाने के लिए समर्थन की दरकार थी, क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका था। इसलिए गठबंधन की सरकार बनी और उस सरकार का बाहर से समर्थन भाजपा और वामपंथी दलों ने किया। यह भी एक अजीब ही अंतर्विरोध था। सरकार का समर्थन भाजपा और वामपंथी एक साथ कर रहे थे। यह विडंबनापूर्ण था और दिखा रहा था कि देश में धर्मनिरपेक्षता की जड़ें कितनी कमज़ोर थीं। सत्ता में भागीदारी के लिए हर तरह की मिकड़म और अवसरवाद का सहारा लेने के लिए भाजपा के साथ वामपंथी भी तैयार थे।

यही वह दौर था जब अयोध्या में राममंदिर का आंदोलन और उन्माद फैला कर भाजपा ने अपनी ताकत बढाई और गिरती-पड़ती, टूटती-बिखरती सरकारों के बाद केंद्र की सत्ता पर काबिज़ हो गई। वीपी सिंह की सरकार के गिरने के बाद जनमोर्चा में शामिल जनता दल के नेताओं की व्यक्तिगत तौर पर सत्ता हासिल करने की महत्त्वाकांक्षा ने दल को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया और आगे चल कर राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, जनता दल, (यूनाइटेड), जनता दल (सेक्युलर) सामने आए। इन दलों ने जो किया है और कर रहे हैं, सबके सामने है। विशुद्ध अवसरवाद, जातिवाद और अल्पसंख्यकवाद के आधार पर काम करने वाले ये दल भले ही सत्ता पाने में सफल रहे हों, पर अगर ये कहा जाए कि इनकी नीतियों ने देश में भगवा के पूर्ण उभार की ज़मीन तैयार की तो ग़लत नहीं होगा। इन दलों ने केन्द्र अथवा राज्यों की सत्ता में रहने के दौरान जो भ्रष्टाचार किया, वह किसी से छुपा नहीं है। लालू जैसे नेता को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल तक जाना पड़ा और मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी, पर इन्हें शर्म नहीं आई। साथ ही, इन नेताओं ने लूट का अपना साम्राज्य कायम रखने के लिये जातिवाद को खुल कर बढावा दिया। भाजपा ने जहां साम्प्रदायिक घृणा फ़ैलाने के साथ दंगे करवाए, वहीं इन दलों ने जाति के आधार पर समाज को बांटने और घृणा फ़ैलाने का काम किया। इसमें वामपंथी दल हमेशा इनके साथ रहे। खास बात तो ये है कि तथाकथित 'जनता परिवार' के कतिपय दल और वामपंथी कांग्रेस सरकार का भी समर्थन करते रहे। लालू-मूलायम की पार्टियां और वामदल ने लगातार कांग्रेस सरकार का समर्थन किया। वहीं, जनता दल (यूनाइटेड) बना कर भाजपा के सहयोग से नीतीश कुमार ने बिहार में लालू यादव के कुनबे में सत्ता से बेदखल कर दिया। नीतीश केन्द्र में भाजपा की सरकार के साथ रहे। पर अब मोदी के कट्टर विरोधी हैं। लोकसभा चुनावों में उन्हें और सपा प्रमुख मुलायम को अपनी हैसियत पता चल गई, तो 'आपदधर्म' के तहत अब लालू को बड़ा भाई मान राजद से गठजोड़ कायम कर लिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे इन्हें फ़ायदा होगा ?

आज नीतीश कुमार भाजपा को साम्प्रदायिक बताते हुए उसे अछूत और दुश्मन मानकर चल रहे हैं, पर क्या भाजपा के साम्प्रदायिक चरित्र के बारे में उन्हें आज पता चला है ? जब भाजपा का नेतृत्व आडवाणी के हाथों में था, तो क्या वह साम्प्रदायिक नहीं थी ? अयोध्या में राममंदिर का अभियान किसने चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ और देश भर में साम्प्रदायिक दंगे हुए। जाहिर है, लालू-मुलायम-नीतीश जैसे नेताओं को साम्प्रदायिकता के ख़तरे से कोई लेना-देना नहीं है, इन्हें तो मतलब है अपनी कुर्सी बचाए रखने से, अब जिस तरह ख़तरा मंडरा रहा है और इसी आसन्न ख़तरे से बचने के लिए ये एक हो रहे हैं। लेकिन क्या इनकी एकता बन भी पाएगी और बनी तो कब तक चल पाएगी, यह सवाल महत्त्वपूर्ण है।

प्रस्तावित समाजवादी जनता दल में जो पार्टियां शामिल हैं, उनका राष्ट्रीय स्तर पर कोई जनाधार नहीं है। ये क्षेत्रीय दल हैं और जातिवादी समीकरणों पर आधारित हैं। बिहार में मुलायम का कोई प्रभाव नहीं, यूपी में नीतीश-लालू का कोई जनाधार और वोटबैंक नहीं। चौटाला को तो हरियाणा में ही कोई पूछनेवाला नहीं। टीचर भर्ती घोटाले में जेल में सज़ा काट रहे हैं। पांव कब्र में लटके हैं और वंशवाद की राजनीति करने वाले चौटाला के परिवार में अब कोई दमदार नेता नहीं जो उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढा सके। ये बिहार और यूपी के चुनावों पर क्या असर डाल पाएंगे, आसानी से समझा जा सकता है।

बिहार में कहने को लालू-नीतीश एक हो चुके हैं, पर सत्ता की महत्त्वाकांक्षा इनके बीच दरार पैदा करती रहेगी। लालू ने खुले तौर पर अपने बेटे को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। नीतीश ने यद्यपि जीतनराम मांझी से सत्ता छीन ली, पर वह भी महादलितों के बीच अपना आधार बनाने की कोशिश में लगे हैं और एक तरफ़ लालू तो दूसरी तरफ़ भाजपा के नेता उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश में लगे हैं। इन क्षत्रपों की राजनीति पूरी तरह जातिवादी समीकरणों और अल्पसंख्यक वोटों पर आधारित है। ऐसे में, इनके बीच ही अंतर्विरोध इतने गहरे हैं कि एक होने के पहले ही घटक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष गहराने लगा है। बात जब झंडे और चुनाव चिह्न की आएगी तो विवाद और संघर्ष होना तय है। एक होने के बाद भी इनके वोट विभाजित ही रहेंगे। फ़िर ये भाजपा की चुनौती का सामना कैसे कर पाएंगे ? ये ऐसे सावल हैं जो महाविलय के सूत्रधार नेताओं के मन में भी कुलबुला रहे हैं और ये बहुत ही उलझन में फ़ंसे हैं।

लोकसभा चुनावों में यूपी में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ़ हो गया। सिर्फ़पांच सीटें मिलीं और वो भी मुलायम परिवार के सदस्यों के ही। यूपी में जंगल राज है। मुलायम ख़ुद अपनी ही सरकार की आलोचना करते रहे हैं। वहीं, उन्होंने जिस राजसी तरीके से अपना जन्मदिन मनाया और सैफ़ई उत्सव पर जनता का करोड़ों रुपया फूंका, उससे भी जनता के सामने उनके समाजवाद की पोल खुल चुकी है। पर जनता तो दुश्चक्र में फंसी हुई है। विकल्प है नहीं। बावजूद ऐसा नहीं लगता कि जनाधार खो चुके ये क्षत्रप एक हो कर भाजपा के विजय रथ को रोक पाएंगे। ये अलग बात है कि बहुत ज़ोर लगाकर ये भाजपा को मिलने वाली सीटों में कुछ कमी ला सकें, पर इनके चरित्र को देखते हुए जनता इन पर भरोसा नहीं कर सकती। इनके लिए अपना बिखरता साम्राज्य बचाए रख पाना मुश्किल होगा।

अब देखना ये कि महाविलय के बाद ये पार्टी जब आकार लेती है तो संगठन में पद आदि को लेकर किस तरह की उठापटक सामने आती है। जहां तक यूपी का सवाल है, सपा के बहुत से नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह महसूस हो रहा है कि एक पार्टी बन जाने से सपा को घाटा होगा। इसकी मुख्य वजह यही है कि कोई भी दल दूसरे राज्य में जनाधार यानी वोटबैंक न हो पाने के कारण एक-दूसरे की मदद करने में कारगर नहीं हो सकेगा। इस महाविलय के पीछे मुलायम सिंह की पुरानी महत्त्वाकांक्षा को भी नहीं भूला जा सकता। मुलायम की चिर अभिलाषा है देश का प्रधानमंत्री बनने की। प्रस्तावित समाजवादी जनता दल का प्रमुख बन कर उन्हें लगता है कि यह सपना पूरा हो सकेगा। पर यह उनका दिवास्वप्न है। यह राजनीतिक समीकरणों से स्पष्ट है। इस महाविलय से नीतीश-लालू-मुलायम को कोई लाभ हो पाना मुश्किल ही दिखाई पड़ता है।

अभी-अभी सीताराम येचुरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नए महासचिव निर्वाचित हुए हैं। इनका कहना है कि जल्दी ही सीपीआई और सीपीएम का विलय होगा। स्वाभाविक है, ये मुलायम-लालू-नीतीश के साथ होंगे। लेकिन जनाधार इनका भी नहीं है। इनका भ्रष्ट चरित्र भी लोगों के सामने जाहिर है। जिस प्रकार मुलायम-लालू-नीतीश नकली समाजवादी हैं, उसी तरह ये भी नकली कम्युनिस्ट हैं। इन्होंने भी पूर्व में सत्ताधारी दलों का समर्थन कर खूब मलाई चाटी है, पर समय अब इनके प्रतिकूल है। ये भी मुलायम-लालू-नीतीश के सपनों के साकार कर पाने में मददगार नहीं हो सकेंगे। जाहिर है, अभी भारतीय राजनीति में विकल्पहीनता का दौर लंबा चलने वाला है। अंधकार की शक्तियां प्रबल हैं। गरीब जनता को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सत्ता में भाजपा है या लालू-मुलायम-नीतीश या वामपंथी। सभी उसके लिये एक जैसे ही साबित हुए हैं। राजनीति में नया प्रयोग कर दिल्ली में सत्ता में आई आद आदमी पार्टी का हश्र भी सबके सामने बहुत जल्दी आ गया। इससे गहरी निराशा का माहौल बना है। लेकिन यह दिखाता है कि पूंजीवादी व्यवस्था का संकट बहुत ही गहरा गया है। फ़िलहाल, सर्वसत्तावादी ताकतों का ही वर्चस्व कायम रहेगा। जब तक आम मेहनतकश जनता विचारधारा के आधार पर संगठित नहीं होती और उसके बीच से नेतृत्व नहीं उभरता, राजनीति में जनविरोधी तत्वों का बोलबाला बना रहेगा। विभ्रम और बिखराव की स्थितियां बनी रहेंगी। आम जनता को बहुत मार झेलनी है। अब नया राजनीतिक संघर्ष जो वास्तव में जनता को उसका हक़ दिलाने के लिए होगा, तो वह वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था जो विश्व साम्राज्यवाद से आबद्ध है, उसके ख़िलाफ़ ही हो सकता है। बीच का कोई रास्ता नहीं है। मौजूदा सभी राजनीतिक दलों के जनता ने आजमा कर देख लिया है और सभी लुटेरे ही साबित हुए हैं।

मतदान के बारे में कुछ विचार

कहा जाता है कि हिन्दुस्तान में लोकतंत्र है परन्तु चुनाव के दौरान कौन-कौन से हथकंडे अपनाकर लोग सत्ता तक पहुंचते हैं। यह सब जानते हैं। आम जनता को बरगलारकर नेता अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। उससे आगे मैं बताना चाहता हूं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। क्या वे ऐसा जानबूझकर करते हैं। या उससे करवाया जाता है। या उसके पीछे कोई छिपी हुई शक्तियां काम कर रही होती हैं। उसमें दो शक्तियां होती हैं। 1.डर 2. लोभ (लालच) 1. डर-इस मामले में होता है कि बड़े-बड़े नामी डकैत या बदमाश तबके के लोग जिनके ऊपर इनाम घोषित होता है उनका सम्पर्क सीधे नेताओं से होता है एवं उनके आस-पास रहने वाले लोगों को वे डरा-धमकाकर रखते हैं और कहते हैं जिसको हम कहेंगे उसे वोट देना नहीं तो तुम्हारा रहना दूभर कर देंगे और तरह-तरह से परेशान करते हैं। एवं उनसे खाना-पीना कपड़े इत्यादि उपयोग का सामान मंगाते रहते हैं। 2. लोभ- लाालच के द्वारा कि तुम्हे पैसा मिलेगा या तुम्हें रोड बनाने का या पुल बनाने का या खडंजा लगाने का ठेका मिलेगा जिसके द्वारा तुम्हारी अच्छी कमाई करवा देंगे या कन्ट्रोल का कोटा मिलेगा जिसमें गेहूं, चावल, चीनी, तेल इत्यादि बेचने के लिये दिया जायेगा उसमें मनचाही कमाई कर लेना। या गैस (एल पी जी) और पेट्रोल पम्प का लाइसेन्स दे दिया जायेगा उसमें मनचाही कमाई कर लेना। नेता भी वे लोग बनते हैं 99 प्रतिशत लोग सिर्फ कमाई करने के लिए। जिसमें करीब-करीब सभी लोग भ्रष्टाचार के द्वारा लोभ के बस में होकर कमाई करते हैं। लोग इस तरह की कमाई क्यों करते हैं। जबकि सभी जानते हैं कि इस तरह की कमाई करने का मतलब होता है गलत रास्ता चुनना और उसी गलत रास्ते के द्वारा कमाकर पैसा घर में लाना। असल में लोग अपनी निजी सम्पत्ति को बढाने में लगे रहते हैं। जितनी अधिक सम्पत्ति हमारे पास होगी उतनी ताकत हमारी बढ़ेगी। वह ताकत होती है कोई भी इस्तेमाल करने की वस्तु को खरीदने की ताकत। यह सम्पत्ति के द्वारा भी हो सकती है और ख्याति के द्वारा भी हो सकती है जितनी हमारी ख्याति बढ़ेगी उतना हमारा वर्चस्व कायम होगा उतनी हमारी बात मानी जायेगी; हमारी हुकूमत चलेगी। उस ताकत के द्वारा हम निर्जीव चीज़ें जैसे गाड़ी, मोटर तो खरीदेंगे ही सभी तरह के जानवर, जीव-जन्तु भी खरीद सकते हैं। आदमी, औरत, बच्चे के साथ में उनकी शारीरिक व मानसिक श्रम शक्ति भी खरीद लेंगे और यहां तक कि सरकारी कर्मचारी, अधिकारी एवं कानून (संविधान) को भी खरीद कर अपने लिये अपने हिसाब से तोड़-मरोड़कर इस्तेमाल कर लेंगे।

दोस्तों! ये पूंजीवाद है। पूंजीवाद के रहते ऐसा ही होगा क्योंकि पूंजी का स्वाभाविक गुण ऐसा ही होता है। यदि हमको जरूरत के हिसाब से उपयोग के संसाधन जुटा कर उसका उचित उपयोग करना है। जिसकी जिस चीज़ के लिये जितनी जरूरत है उतना लें या उसको उतना ही मिले और शारीरिक क्षमता व मानसिक क्षमता भर काम लिया जाए। जैसे जन्म से लेकर मृत्यु तक भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, हवादार मकान की उचित व्यवस्था हो तो उसके लिए हमें पूंजी के स्वभाव को जानना समझना होगा।

पूंजी के इतिहास को समझना होगा कि इससे पहले पूंजी ने क्या-क्या, कैसे-कैसे किया। फ़िर एकता की ताकत बानाकर उसके दम पर। लोकतंत्र के झूठे आडम्बर को सिरे से नकारना होगा। और श्रमिकों का राज समाजवाद की स्थापना करनी होगी। और उसके द्वारा साम्यवाद लाना होगा।

-नागरिक